Hindustan Times - 29- January-2024

Water resources may get 10% more in FY25

Puja Das

puja.das@livemint.com

NEW DELHI: The department of water resources, river development and Ganga rejuvenation may get a 10% more in the interim budget for continuing with marquee projects such as linking the Ken and Betwa rivers, dam rehabilitation and improvement, infrastructure rehabilitation, Namami Gange and Atal Bhujal Yojana, a senior official said.

In the FY24 budget, the department received an allocation of ₹20,055 crore, which may be hiked to a little over ₹22,000 crore. "As of now I think the interim budget will be more

about carrying on with the current work that is happening unless there are some major SOPs," the official said.

"We are expecting a normal 10% increase in our budgetary allocation. The work we are doing will be continued. In the Ken-Betwa project, the land acquisition is almost complete. So, this will be funded fully. There is the dam rehabilitation and improvement programme that the states are working on. We have funding for the rehabilitation of large water infrastructure, which is picking up pace.

We have the participatory groundwater management programme—Atal Bhujal Yojana which is fully funded. There again a lot of work is happening. Mostly sanctions have been issued for Namami Gange. The main river has been saturated (in terms of resources), and now we are moving to tributaries as a priority. That work will also get the resources that it needs.

We are in an agreement that we will get the resources that we need to fund larger projects to ensure that project implementation is not hampered," the official added.

Queries sent to the departments of water resources, river development and Ganga rejuvenation and expenditure remained unanswered at press time.

Atal Bhujal Yojana, a ₹6,000

crore central sector scheme, was launched in 2019 aiming at sustainable management of groundwater with community participation.

With an additional outlay of ₹8.000 crore, the Centre is also planning to extend the scheme to Punjab, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh as they are found to be waterstressed and the proposal is with the finance ministry, the official disclosed. Currently, the Atal Bhujal scheme is being implemented by the Jal Shakti ministry in 8,220 water-stressed village Panchayats of Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh.

Millennium Post - 29- January-2024

Snowfall likely in western Himalayas, cold wave to continue in plains: IMD

NEW DELHI: The India Meteorological Department (IMD) issued a weather alert on Sunday, predicting a wet spell over the western Himalayan region until February 3. The forecast included the possibility of isolated heavy snowfall on January 30 and 31, particularly in Kashmir and Himachal Pradesh. Dense fog and frigid temperatures are also expected to continue over Uttar Pradesh and Bihar for the next two days, gradually improving thereafter.

According to the daily bulletin from the weather forecast agency, two consecutive Western Disturbances are projected to impact northwest India starting from January 30, with another expected from February 3.

"Under the influence of



these systems, there is a high probability of light to moderate scattered to fairly widespread rainfall/snowfall over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, and Himachal Pradesh in the next seven days," stated the IMD.

Additionally, isolated heavy rainfall/snowfall is expected over Kashmir on January 30 and January 31, and over Himachal Pradesh on January 31.

The IMD added, "Light/ moderate isolated to scattered rainfall/snowfall is very likely over Uttarakhand, with light rainfall expected over Punjab, Chandigarh, Haryana, and West Uttar Pradesh during January 31 and February 2."

Continued on P4

Snowfall likely

Furthermore, the IMD reported that minimum temperatures are ranging from 6-9 degrees Celsius over many parts of the plains of Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, and Madhya Pradesh. In Rajasthan, temperatures are in the range of 8-10 degrees Celsius.

"These temperatures are below normal by 3-6 degrees Celsius over many parts of the plains of Bihar and East Uttar Pradesh, and in the range of 1-3 degrees Celsius over Haryana, Chandigarh, West Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal, and north Chhattisgarh. Today, the lowest minimum temperature of 5.2 degrees Celsius was reported at Gorakhpur (East Uttar Pradesh)," informed the IMD.

Dainik Bhaskar - 29- January-2024

ईआरसीपी-पीकेसी • सरकार बनने के बाद सवा माह में राजस्थान-एमपी में विवाद खत्म

20 साल का विवाद ७ घंटे में दूर, पार्वती-कालीसिंध-चम्बल जुड़ेंगी, 32 बांध भरेंगे

2017 से राजस्थान व एमपी के बीच विवाद के चलते चुनावी मुद्दा रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का हल रविवार को 7 घंटे में निकल आया। यह संभव हुआ केंद्र सरकार की पहल पर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दखल पर एमपी के सीएम मोहन यादव रविवार को जयपुर पहुंचे और सीएम भजनलाल शर्मा से मिले। इसके बाद शेखावत के बलावे पर दोनों राज्यों के अफसरों के साथ दोनों सीएम दिल्ली पहुंचे, जहां एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर संशोधित प्रोजेक्ट पर हुए हैं, जिसे केंद्र की नदी जोडो परियोजना में शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट अब पार्वती-कालीसिंध-चम्बल पूर्वी राजस्थान नहर लिंक परियोजना (पीकेसी-इंआरसीपी) के रूप में आकार लेगा। इसके लिए 90% राशि केंद्र देगा।

संतुष्टि है, मेरे जीते जी होगा : किरोड़ी

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा-इस प्रोजेक्ट का मूर्त रूप लेना मेरे लिए सपना साकार होने जैसा है। संतुष्टि है कि मेरे जीते जी यह प्रोजेक्ट आकार लेगा। मोदी जी की एक और गारंटी पूरी हुई। -शेष | पेज 5

भारकर Explainer • ईआरसीपी पर वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

वो ७ घंटे...दोपहर को यादव जयपुर आए, शाम को दोनों सीएम दिल्ली पहुंचे, रात को एमओयू



हाथ जुड़ें, अब निदयां जुड़ेंगी सरकार लाओ, मैं इंआरसीपी दूंगा। अब कहा, यह स्वर्णिम दिन है।

• दोपहर 1 बजे : एमपी के सीएम मोहन यादव जयपुर पहुंचे, सीएम भजनलाल शर्मा से मिले।

• शाम 6 बजे : केंद्रीय जल शिक्त मंत्री शेखावत के बुलावे पर दोनों मख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे।

• रात 8 बजे : दिल्ली में संशोधित प्रोजेक्ट के एमओयू पर हस्ताक्षर। सीएम भजनलाल बोले- प्रोजेक्ट समय पर पुरा करवाएंगे।

राजस्थान को ये लाभ

- 2.80 लाख हेक्टेबर में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। इसमें 80 हजार हेक्टेबर पूर्व सिंचित क्षेत्र और 2 लाख हेक्टेबर नया क्षेत्र।
 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई
- का पानी और राज्य की 40% आबादी को पेयजल मिल संकेगा।
- 13 दिसंबर 2022 को केंद्र ने पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को ईआरसीपी से जोड़ने के प्रस्ताव को प्रायमिकता वाली लिंक परियोजना में शामिल किया था।
- 32 बांध भरे जा सकेंगे। इनमें रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरे बांध, पूर्वीनमिंत 26 बांधों का पुनरोद्धार होगा।

पहले सिर्फ राजस्थान, अब दोनों राज्यों के 13-13 जिले

- पहले : केवल राजस्थान के 13 जिलों में पानी पहुंचाना था।
- अब : राजस्थान-एमपी दोनों के 13-13 जिलों में पानी पहुंचेगा।

सीधी बात • केंद्रीय जलशक्ति मंत्री शेखावत से

एमओयू इतना आसान था तो अब तक प्रोजेक्ट क्यों अटका रहा? ■ वर्ष 2004 में अटलजी के समय नदियां जोड़ने के लिए जो प्रस्ताव बने तो देश में 30 लिंक चिह्नित हुए थे। उनमें राजस्थान-एमपी के बीच पार्वती, कालीसिंध व चंबल को जोड़ना भी शामिल था। लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमित नहीं बन पाई थी।

सिर्गोधित प्रोजेवर से तो राजस्यान को पानी कम मिलेगा? • नहीं। गहलोत सरकार ने सिर्फ सियासत की। जो डीपीआर बनवाई, उसमें सिर्फ 3 जिलों को 525 एमसीएम पानी मिलना था। दस जिले वंचित रख दिए थे। अब दोनों राज्यों के 2400-2400 एमसीएम पानी मिलेगा। (जैसा आलोक खण्डेलवाल को बताया)

20 साल का विवाद...

यह था विवाद... गहलोत सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग करते हुए इसे मुद्दा बनाए रही। इसके लिए 75% डिपेंडिबिलिटी पर डीपीआर बनना जरूरी था, लेकिन सरकार 50% पर लागू करने पर अड़ी थी। ऐसे में राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जा सका। अब यूं हल... शेखावत ने संशोधित प्रोजेक्ट पर दोनों राज्यों के अफसरों के साथ बैठकें कर पहले ही सहमति बना ली थी। सीएम भजनलाल के शपथ ग्रहण के दौरान एमपी के सीएम यादव से बात की। यादव ने आश्वस्त किया था कि जिस दिन बैठेंगे, एक ही बार में बाधाएं दूर हो जाएंगी।